WITWAVES
JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
Vol-2 Issue-5
(International Peer-Reviewed E-Journal)
(May 2025)

प्रत्यक्ष कर सुधार और व्यापारिक पारदर्शिता

डॉ. मनीष कांत
सह-प्राध्यापक

सारांश

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की राजकोषीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। प्रत्यक्ष करों के माध्यम से सरकार आय, लाभ और संपत्ति पर कर लगाकर राजस्व एकत्रित करती है तथा उसे आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण, आधारभूत संरचना और सार्वजनिक सेवाओं पर व्यय करती है। भारत में प्रत्यक्ष कर प्रणाली का प्रमुख आधार आयकर अधिनियम, 1961 है, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत आयकर, कॉर्पोरेट कर, पूंजीगत लाभ कर तथा अन्य प्रत्यक्ष करों का निर्धारण किया जाता है। समय के साथ बदलते आर्थिक परिवेश, वैश्वीकरण, डिजिटलीकरण और निवेश-अनुकूल वातावरण की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने प्रत्यक्ष कर प्रणाली में अनेक सुधार लागू किए हैं।

प्रत्यक्ष कर सुधारों का प्रमुख उद्देश्य कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी, न्यायसंगत और उत्तरदायी बनाना है। हाल के वर्षों में फेसलेस असेसमेंट, ई-फाइलिंग, डिजिटल कर प्रशासन, करदाताओं का चार्टर, कॉर्पोरेट कर दरों में कमी, कर विवाद समाधान योजनाएँ तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित अनुपालन तंत्र जैसे सुधारों ने कर प्रशासन को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया है। इन सुधारों से कर चोरी, भ्रष्टाचार और अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप में कमी आई है तथा करदाताओं का विश्वास बढ़ा है।

व्यापारिक पारदर्शिता आधुनिक कॉर्पोरेट प्रशासन का एक प्रमुख तत्व है। पारदर्शी कर प्रणाली व्यवसायों को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, बेहतर निवेश वातावरण, विदेशी निवेश आकर्षण तथा सुशासन के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरी ओर जटिल कर कानून, अनुपालन लागत, कर विवाद तथा बार-बार होने वाले संशोधन व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं।

यह शोध पत्र भारत में प्रत्यक्ष कर सुधारों की पृष्ठभूमि, प्रमुख सुधारों, व्यापारिक पारदर्शिता पर उनके प्रभाव, कॉर्पोरेट प्रशासन, कर अनुपालन, डिजिटल कर प्रशासन, चुनौतियों तथा भविष्य की संभावनाओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि प्रभावी प्रत्यक्ष कर सुधार न केवल सरकारी राजस्व में वृद्धि करते हैं, बल्कि व्यवसायों में विश्वास, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को भी सुदृढ़ बनाते हैं।

बीज-शब्द

प्रत्यक्ष कर, कर सुधार, व्यापारिक पारदर्शिता, आयकर, कॉर्पोरेट कर, फेसलेस असेसमेंट, ई-फाइलिंग, कर अनुपालन, डिजिटल कर प्रशासन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस।

1. प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति उसके कर ढाँचे की दक्षता, पारदर्शिता और न्यायसंगतता पर निर्भर करती है। प्रत्यक्ष कर प्रणाली सरकार के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत होने के साथ-साथ आर्थिक असमानताओं को कम करने, संसाधनों के पुनर्वितरण तथा सामाजिक न्याय की स्थापना का प्रभावी माध्यम भी है।

भारत में आर्थिक उदारीकरण (1991) के बाद कर सुधारों की प्रक्रिया तेज हुई। इसके अंतर्गत कर दरों का युक्तिकरण, कर आधार का विस्तार, डिजिटल कर प्रशासन, कर चोरी पर नियंत्रण तथा निवेश-अनुकूल वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से अनेक सुधार किए गए। हाल के वर्षों में आयकर विभाग द्वारा फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील, ऑनलाइन कर भुगतान, ई-फाइलिंग, पूर्व-भरे हुए (Pre-filled) आयकर रिटर्न तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित जोखिम विश्लेषण जैसी व्यवस्थाओं ने कर प्रशासन को अधिक पारदर्शी बनाया है।

व्यापारिक पारदर्शिता का अर्थ है कि व्यवसाय अपनी वित्तीय, कर संबंधी एवं नियामकीय गतिविधियों का सही, पूर्ण और समयबद्ध प्रकटीकरण करें। पारदर्शिता से निवेशकों, उपभोक्ताओं, सरकार तथा अन्य हितधारकों का विश्वास बढ़ता है और व्यवसाय का दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित होता है।

2. शोध के उद्देश्य

1. प्रत्यक्ष कर प्रणाली की अवधारणा एवं स्वरूप का अध्ययन करना।
2. भारत में प्रत्यक्ष कर सुधारों का विश्लेषण करना।
3. व्यापारिक पारदर्शिता पर कर सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
4. डिजिटल कर प्रशासन की भूमिका का अध्ययन करना।
5. कर अनुपालन एवं कॉर्पोरेट प्रशासन के संबंध का विश्लेषण करना।
6. भविष्य के सुधारों हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

3. शोध-विधि

यह अध्ययन वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है।

अध्ययन के स्रोत

प्राथमिक स्रोत

आयकर अधिनियम, 1961

वित्त अधिनियम

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की अधिसूचनाएँ

प्रत्यक्ष कर संबंधी सरकारी दिशानिर्देश

द्वितीयक स्रोत

वित्त मंत्रालय की रिपोर्टें

आर्थिक सर्वेक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

नीति आयोग

OECD एवं IMF की रिपोर्टें

शोध पत्र, पुस्तकें एवं जर्नल

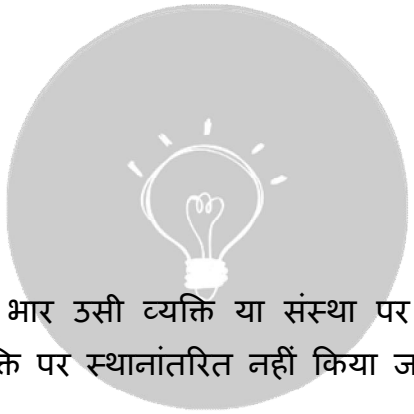

4. प्रत्यक्ष कर की अवधारणा

प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका भार उसी व्यक्ति या संस्था पर पड़ता है जिस पर सरकार कर लगाती है। इसे किसी अन्य व्यक्ति पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।

प्रमुख प्रत्यक्ष कर

आयकर (Income Tax)

कॉर्पोरेट कर (Corporate Tax)

पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax)

5. भारत में प्रत्यक्ष कर सुधार

भारत में समय-समय पर निम्न प्रमुख सुधार किए गए—

(1) कर दरों का युक्तिकरण

कॉर्पोरेट कर की दरों में कमी कर निवेश को प्रोत्साहित किया गया।

(2) फेसलेस असेसमेंट

कर निर्धारण प्रक्रिया को ऑनलाइन एवं निष्पक्ष बनाया गया।

(3) फेसलेस अपील
मानवीय हस्तक्षेप एवं भ्रष्टाचार की संभावना कम हुई।

(4) ई-फाइलिंग प्रणाली
कर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया सरल एवं तेज हुई।

(5) Taxpayers' Charter
करदाताओं के अधिकारों एवं दायित्वों को स्पष्ट किया गया।

(6) डिजिटल भुगतान
ऑनलाइन कर भुगतान एवं डिजिटल रिकॉर्ड से पारदर्शिता बढ़ी।

6. व्यापारिक पारदर्शिता की अवधारणा

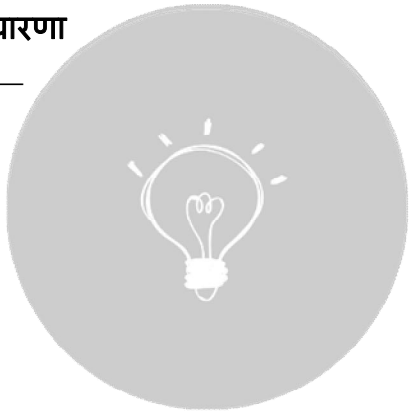

व्यापारिक पारदर्शिता का अर्थ है—
सही वित्तीय विवरण
समय पर कर भुगतान
नियामकीय अनुपालन
लेखा मानकों का पालन
ईमानदार व्यापारिक व्यवहार

7. प्रत्यक्ष कर सुधारों का व्यापारिक पारदर्शिता पर प्रभाव

(क) सकारात्मक प्रभाव

1. भ्रष्टाचार में कमी
डिजिटल कर प्रशासन से व्यक्तिगत संपर्क कम हुआ।

2. निवेशकों का विश्वास
पारदर्शी कर व्यवस्था विदेशी एवं घरेलू निवेश आकर्षित करती है।

3. कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार
कर अनुपालन से सुशासन को बढ़ावा मिला।

4. कर चोरी में कमी

डेटा एनालिटिक्स एवं सूचना साझाकरण से कर अपवंचन पर नियंत्रण हुआ।

5. Ease of Doing Business
सरल कर प्रक्रियाओं से व्यापार करना आसान हुआ।

(ख) नकारात्मक प्रभाव
अनुपालन लागत में वृद्धि
तकनीकी चुनौतियाँ
छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल कठिनाइयाँ
बार-बार कर संशोधन से अनिश्चितता

8. डिजिटल कर प्रशासन
भारत में डिजिटल कर प्रशासन के प्रमुख घटक—
ई-फाइलिंग पोर्टल
फेसलेस असेसमेंट
फेसलेस अपील
ऑनलाइन नोटिस
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जोखिम विश्लेषण
डेटा एनालिटिक्स

9. कॉर्पोरेट प्रशासन और कर पारदर्शिता
उत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए आवश्यक है—
सही लेखांकन
वैधानिक ऑडिट
समय पर कर भुगतान
पारदर्शी वित्तीय रिपोर्टिंग
नियामकीय अनुपालन

10. प्रमुख चुनौतियाँ
जटिल कर कानून
लंबित कर विवाद

डिजिटल साक्षरता की कमी
साइबर सुरक्षा जोखिम
अंतरराष्ट्रीय कराधान की जटिलताएँ
कर चोरी के नए तरीके

11. सुधार हेतु सुझाव

1. प्रत्यक्ष कर कानूनों का सरलीकरण किया जाए।
2. Direct Tax Code (DTC) जैसे व्यापक सुधारों पर विचार किया जाए।
3. MSMEs के लिए अनुपालन लागत कम की जाए।
4. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कर प्रशासन को और सुदृढ़ किया जाए।
5. कर विवादों के शीघ्र समाधान हेतु प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए।
6. करदाताओं के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएँ।
7. कर नीति को दीर्घकालिक एवं स्थिर बनाया जाए।

12. भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष कर सुधारों का महत्व

राजस्व वृद्धि
निवेश आकर्षण
व्यापारिक पारदर्शिता
सुशासन
भ्रष्टाचार में कमी
कर आधार का विस्तार
आर्थिक विकास
वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि

निष्कर्ष

प्रत्यक्ष कर सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हैं। इन सुधारों ने कर प्रशासन को तकनीक-सक्षम, करदाता-केंद्रित और अधिक दक्ष बनाया है। फेसलेस असेसमेंट, ई-फाइलिंग, डिजिटल भुगतान, Taxpayers' Charter तथा डेटा-आधारित निगरानी जैसे उपायों ने कर अनुपालन को बढ़ावा दिया है और भ्रष्टाचार तथा कर अपवंचन की संभावनाओं को कम किया है।

व्यापारिक पारदर्शिता केवल कानूनी अनुपालन का विषय नहीं है, बल्कि यह निवेशकों के विश्वास, कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक व्यावसायिक सफलता का आधार भी है। एक पारदर्शी कर व्यवस्था से निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन तथा आर्थिक विकास को बल मिलता है। हालांकि जटिल कर कानून, अनुपालन लागत, लंबित विवाद और डिजिटल चुनौतियाँ अभी भी सुधार की मांग करती हैं।

भविष्य में एक सरल, स्थिर, पूर्वानुमेय और पूर्णतः डिजिटल प्रत्यक्ष कर प्रणाली भारत को निवेश-अनुकूल वातावरण प्रदान करने, व्यवसायों में विश्वास बढ़ाने तथा "विकसित भारत" के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसलिए कर सुधारों को निरंतर आगे बढ़ाते हुए पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और तकनीकी नवाचार को कर प्रशासन का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. आयकर अधिनियम, 1961।
2. वित्त अधिनियम (विभिन्न वर्ष), भारत सरकार।
3. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), वार्षिक रिपोर्ट एवं अधिसूचनाएँ।
4. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय।
5. आर्थिक सर्वेक्षण, भारत सरकार।
6. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), Report on Currency and Finance।
7. नीति आयोग, भारत सरकार।
8. OECD. Tax Administration and Tax Policy Reforms.
9. International Monetary Fund (IMF). Fiscal Monitor.
10. Singhania, V.K. & Singhania, M. Direct Taxes Law and Practice.
11. Ahuja, Girish & Gupta, Ravi. Systematic Approach to Income Tax.
12. ICAI. Study Material on Direct Tax Laws.
13. विश्व बैंक की कर प्रशासन एवं व्यावसायिक वातावरण संबंधी रिपोर्टें।
14. विभिन्न शोध पत्र एवं राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय जर्नल।